आकाशवाणी
क्षेत्रीय समाचार
देहरादून (उत्तराखण्ड)
शुक्रवार 06.03.2026
समय 1305

मुख्य समाचार :–

- प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू।
- राज्य में आयुष्मान योजना के तहत अब तक 17 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया गया।
- मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई जल जीवन मिशन से संबंधित सर्वोच्च समिति की बैठक। मिशन की प्रगति, वित्तीय स्थिति और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई।
- प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों को राशन आपूर्ति करने वाले रुड़की स्थित गोदाम पर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने छापेमारी की।

चारधाम पंजीकरण

प्रदेश में आगामी चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू हो गए हैं।

चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण आज सुबह सात बजे से शुरू हो गया है। श्रद्धालु पर्यटन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट registrationandtouristcare.uk.gov.in तथा मोबाइल ऐप टूरिस्ट केयर उत्तराखंड के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल ने बताया कि इस वर्ष चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। इसी दिन यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को और बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भारतीय श्रद्धालु आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण कर सकेंगे, जबकि विदेशी श्रद्धालुओं के लिए ई–मेल आईडी के जरिए पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पाएंगे, उनके लिए ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह सुविधा 17 अप्रैल से शुरू की जाएगी। इसके लिए ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान और विकासनगर में विशेष पंजीकरण काउंटर स्थापित किए जाएंगे। प्रशासन के अनुसार चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं।

आयुष्मान योजना

प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत अब तक 17 लाख से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। इस पर राज्य सरकार, तीन हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च कर चुकी है। वहीं, 'प्रधानमंत्री वय वंदना योजना' के तहत राज्य में 25 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के कार्ड बनाए जा चुके हैं, जिनमें से 11 हजार से अधिक बुजुर्गों ने इस योजना के तहत निःशुल्क उपचार का लाभ उठाया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार आम लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर उपलब्धता के कारण अधिक से अधिक लोग, सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार, कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी योजना संचालित कर रही है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 57 लाख और एसजीएचएस योजना के तहत पांच लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना से सूचीबद्ध अस्पतालों में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को भी निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। दुर्घटना में घायलों के उपचार के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की कैशलेस सुविधा केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही है।

सैन्य अभ्यास

अल्मोड़ा जिले के चौबट्टिया में भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्डियन' जारी है। नौ मार्च तक चलने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों के 120–120 सैनिक भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य साझा सुरक्षा चुनौतियों और वैश्विक आतंकवाद के खतरे को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ–डिफेंस फोर्स के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। अभ्यास के दौरान उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना, आपसी समन्वय और वास्तविक फील्ड परिस्थितियों में सामरिक अभ्यासों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा अस्थायी ऑपरेटिंग बेस की स्थापना, मोबाइल वाहन चेक पोस्ट, शत्रुतापूर्ण वातावरण में घेराबंदी और तलाशी अभियान, हेलिबोर्न ऑपरेशन और हाउस इंटरवेंशन ड्रिल जैसे अभ्यास किए जा रहे हैं।

जल जीवन मिशन

मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई जल जीवन मिशन से संबंधित सर्वोच्च समिति की बैठक में राज्य में मिशन की प्रगति, वित्तीय स्थिति और आगामी कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने पानी की गुणवत्ता परीक्षण में रासायनिक और जीवाणु संबंधी परीक्षण अनिवार्य रूप से कराने और परीक्षण की जानकारी संबंधित योजना में तिथि सहित सार्वजनिक हित में स्पष्ट रूप से अंकित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में जीआईएस मैपिंग, पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर पाइपलाइन नेटवर्क अपलोड की प्रगति, सुजल गांव आईडी निर्माण, वित्तीय

समन्वय और तकनीकी निरीक्षण की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने इन सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। वहीं वर्ष 2026–27 की वार्षिक कार्ययोजना, सामाजिक अंकेक्षण और तीसरे–पक्ष निरीक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को इन विषयों पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार से संबंधित सभी बिंदुओं पर समयबद्ध रिपोर्टिंग तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

गोदाम छापा

प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरित की जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर मिल रही शिकायतों पर देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने रुड़की स्थित सेंट्रल गोदाम पर छापेमारी की। यह गोदाम गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के आंगनबाड़ी केंद्रों को राशन आपूर्ति करता है। निरीक्षण के दौरान गोदाम में बाल श्रमिकों से काम कराए जाने का मामला भी सामने आया। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल गोदाम स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए। जांच के दौरान खजूर और केले के चिप्स के पैकेटों पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट संदिग्ध पाई गईं। इसके अलावा दिसंबर और जनवरी में आए अंडों सहित अन्य खाद्य सामग्री को मार्च महीने में वितरित किए जाने की तैयारी पाई गई, जिससे उनकी गुणवत्ता पर संदेह और गहरा गया। छापेमारी के दौरान जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भेजे जा रहे वाहनों को भी मौके पर रुकवाया और उनमें लदी खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए सील कराए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने पूरे मामले की जांच के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि राज्य के नौनिहालों और धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मानक ब्यूरो

उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों, कर्तव्यों और गुणवत्तायुक्त व प्रमाणित उत्पादों के महत्व के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भारतीय मानक ब्यूरो–बीआईएस, देहरादून की ओर से हरिद्वार में ''उपभोक्ता जागरुकता भारत यात्रा'' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को उपभोक्ता अधिकारों, गुणवत्तायुक्त उत्पादों की पहचान, आईएसआई मार्क, हॉलमार्किंग और उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। वक्ताओं ने उपभोक्ताओं से हमेशा प्रमाणित और मानकयुक्त उत्पादों का ही उपयोग करने की अपील की, ताकि उनकी सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। बीआईएस के निदेशक व शाखा प्रमुख सौरभ तिवारी ने प्रतिभागियों को बीआईएस की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी।

गणे□ा जो□ी

ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में अधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान ग्राम्य विकास मंत्री ने केंद्र पोषित योजनाओं में बीवी जी रामजी, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की प्रगति पर चर्चा की। इसके साथ ही राज्य वित्त पोषित योजनाओं – मेरा गांव मेरी सड़क, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना और एकीकृत आजीविका सहायता परियोजना के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए कार्यों में तेजी लाते हुए निर्धारित समयसीमा में योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। बैठक के दौरान 'हाउस ऑफ हिमालयाज' ब्रांड के उत्पादों को आर्मी की कैंटीन में उपलब्ध कराने के विषय में भी चर्चा की गई, ताकि प्रदेश के स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिल सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।